वशिष्ठ नारायण कुमार

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(2024 का दीवानी अपील संख्या 1)

02 जनवरी 2024

[जे के माहेश्वरी और के. वी. विश्वनाथन न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

क्या आवेदन पत्र में की गई कोई त्रुटियां, जो अपलोड की गई थी, एक भौतिक त्रुटियां है या एक तुच्छ त्रुटियां है और क्या राज्य ने अपीलार्थी को उसी के कारण विफल घोषित करने में उचित ठहराया था।

हेड नोट्स

सेवा कानून-भर्ती-आवेदन पत्र में अनजाने में त्रुटियां-अंतिम परिणाम विफल हो गया-अपीलार्थी ने पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया-उसने लिखित परीक्षा और शारीरिक पात्रता परीक्षा पास कर ली-हालाँकि, अंतिम परिणाम ने उसे विफल के रूप में दिखाया-एकमात्र कारण यह था कि ऑनलाइन अपलोड किया गया आवेदन पत्र, अपीलार्थी की जन्म तिथि 08.12.1997 के रूप में दिखाई गई थी, स्कूल की अंकपत्र में, उसकी जन्म तिथि 18.12.1997 के रूप में दिखाई गई थी-स्वामित्वः

माना किः अपीलार्थी के आवेदन में जन्म तिथि का उल्लेख 08.12.1997 के रूप में किया गया था, जबकि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज उसकी जन्म तिथि 18.12.1997 थी-यह भी निर्विवाद है कि यह अपीलार्थी ही है जिसने शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे-वह अपने

आवेदन पत्र में आई त्रुटियां से अनजान था-मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि त्रुटियां इतनी गंभीर थी कि गलत या भ्रामक जानकारी का गठन करती है-मामूली त्रुटियांयों या चूक के लिए एक अपवाद है क्योंकि कानून खुद को छोटी-मोटी बातों से संबंधित करता है-इस सिद्धांत को कानूनी उक्ति-डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स में मान्यता प्राप्त है-इसके अलावा, स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी ने कोई लाभ नहीं मिला, भले ही इसमे से कोई भी तारीख ली गई हो, वह पात्र था, त्रुटि का चयन प्रक्रिया पर कोई असर नही पड़ा, जिस पृष्ठभूमि में त्रुटि हुई, उसे ध्यान में रखते हुए, रद्दीकरण को रद्द कर दिया गया है और प्रतिवादी राजय को अपीलकर्ता को एक उम्मीदवार के रुप मे मानने का निर्देश दिया गया है जो चयन प्रक्रिया में उत्तीर्ण हो गया है।[कंडिका 11,12,15,25,26]

<u>उद्धरणों और अन्य संदर्भों की सूची</u>

योगेश कुमार और अन्य बनाम एन. सी. टी. सरकार, दिल्ली और अन्य, **[2003] 2 एससीआर 662:(2003) 3 एससीसी 548-प्रतिष्ठित/विख्यात।**

दिव्या बनाम भारत संघ और अन्य, **2023 आई. एन. एस. सी. 900:2023 (13) स्केल 730;** प्रिंस जयबीर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य **उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया 2021 का सी. ए. सं. 6983-निर्दिष्ट।**

रोहित कुमार और एक अन्य बनाम भारतीय संघ और अन्य, **2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 1219;** प्रदीप कुमार बनाम भारत संघ और अन्य, **2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 239 - प्रतिष्ठित/विख्यात**

अजय कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ और अन्य, **[2016] एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 6563;** अर्क्षित कपूर बनाम भारत संघ, **2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल**

10154; अनुज प्रताप सिंह बनाम संघ लोक सेवा आयोग, **2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 10982;** के. संगीता बनाम तमिलनाडु लोक सेवा आयोग **(2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 5075;** शुभम तुशीर बनाम भारत संघ, **2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 9831;** कर्मचारी चयन आयोग और एक अन्य बनाम शुभम तुशीर, **2020 का एल.पी.ए. संख्या- 237;** पूनम पाल बनाम एमपी ग्रामिण बैंक, **(2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 2921;** पंकज पासवान बनाम बिहार राज्य और एक अन्य, **2015 एस. सी. सी. ऑन लाइन पटना 8739-संदर्भित।**

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान-अनुच्छेद 142

मुख्य शब्दों की सूची

सेवा कानून; भर्ती; आवेदन पत्र; अनजाने में त्रुटि; यह कम से कम सही नहीं है।

आक्षेपित आदेश और उपस्थिति सहित अन्य मामले का विवरण

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार 2024 की सिविल अपील संख्या 1

2019 के एल. पी. ए. सं.- 1271 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांकित 22.08.2022 के निर्णय और आदेश से।

उपस्थितिः

शिवम सिंह, सुश्री शास्वती पारही, गोपाल सिंह, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्तागण.

अज़मत हयात अमानुल्लाह, तिरुपति गौरव शाही, अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय/आदेश

निर्णय

के. वी. विश्वनाथन न्यायमूर्ति

1. अनुमति दी गई।

2. वशिष्ठ नारायण कुमार (अपीलार्थी) बिहार के धेओधा नामक एक छोटे गाँव के रहने वाले हैं। वे समाज के दलित वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। वह एक पुलिस सिपाही बनने का इच्छुक था और उसने आरक्षित श्रेणी के तहत उक्त पद के लिए आवेदन किया था। इंटरमीडिएट (10+2 पास) होने की पात्रता मानदंड रखने के बाद, उन्होंने लिखित परीक्षा और शारीरिक पात्रता परीक्षा भी पास की।

3. अपीलार्थी ने दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र/मार्कशीट के साथ-साथ अपना जाति प्रमाण पत्र भी जमा किया। 11.06.2018 को, अंतिम परिणामों ने उन्हें विफल होने के रूप में दर्शाया। इसका एकमात्र कारण यह था कि ऑनलाइन अपलोड किए गए आवेदन पत्र में उनकी जन्म तिथि 08.12.1997 के रूप में दिखाई गई थी, जबकि स्कूल की मार्कशीट में उनकी जन्म तिथि 18.12.1997 के रूप में दिखाई गई थी।

4. परेशान, अपीलार्थी ने प्रतिनिधित्व किया और उसके बाद कोई प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रहने पर, उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उनकी व्याख्या सरल और सीधी थी। उन्होंने अपनी रिट याचिका में कहा कि केंद्रीय चयन बोर्ड द्वारा 29.07.2017 को जारी विज्ञापन को देखने के बाद, वह अपने दूरदराज के ग्राम से पास के शहर पाकरीबरावन में साइबर कैफे गए। साइबर कैफे चलाने वाले एक व्यक्ति की सहायता से, उसने अपना फॉर्म भरा और इसे ऑनलाइन अपलोड किया और उसे आवेदन संख्या 7236126 प्राप्त हुआ जो दर्शाता है कि ऑनलाइन आवेदन विधिवत भरा गया था। उनका

मामला यह था कि फॉर्म भरते समय, एक अनजाने में हुई त्रुटियां के कारण, जन्म तिथि "18.12.1997" के बजाय "08.12.1997" के रूप में दर्ज की गई थी। उन्हें इससे कोई लाभ नहीं मिला क्योंकि किसी भी तरह से उन्होंने पात्रता मानदंड और आयु की आवश्यकता को पूरा किया। उन्होंने उत्तरदाताओं से अनुरोध किया कि वे चयन के लिए उनके दावे पर विचार करें और उन्हें जन्म तिथि को 18.12.1997 मानते हुए एक नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दें, जैसा कि उनके शैक्षिक प्रमाणपत्रों में परिलक्षित होता है।

5. प्रत्यर्थियों ने रिट याचिका का जोरदार विरोध किया। यह उनका रुख था कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उम्मीदवारों को अपने 10वें बोर्ड प्रमाण पत्र के अनुसार अपनी जन्म तिथि का सही उल्लेख करना चाहिए; कि यदि जानकारी का मिलान करते समय कोई विसंगति पाई जाती है, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी; कि उम्मीदवार निर्देशों को ध्यान से पढ़े और यदि कोई जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है, तो आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यह आगे कहा गया कि विज्ञापन में सुधार करने की विधि का भी उल्लेख किया गया है और अपीलार्थी ने कभी भी उस सुविधा का लाभ नहीं उठाया।

6. उन्होंने तर्क दिया कि विज्ञापित 9900 रिक्तियों में से 9839 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उपयुक्त गोरखा उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण 61 रिक्तियां खाली रह गई हैं। उन्होंने रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की।

7. विद्वत एकल न्यायाधीश ने विज्ञापन में खंडों का उल्लेख करने के बाद, जिसमें सुधार का प्रावधान करने वाला खंड भी शामिल है, कहा कि चूंकि गलत जानकारी प्रदान की गई थी, इसलिए कोई राहत नहीं दी जा सकती है। अपीलार्थी ने खंड पीठ में एल.पी.ए. दायर की, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल

न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त रूप से एक निष्कर्ष दर्ज किया कि अपीलार्थी ने वेबसाइट पर 11.06.2018 को घोषित परिणाम को रद्द करने की मांग नहीं की थी।

8. व्यथित होने के कारण, अपीलार्थी इस अपील में हमारे सामने है।

9. हमने अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री शास्वती पारही और राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री अजमत हयात अमानुल्लाह को सुना है। विद्वान वकीलों ने नीचे दिए गए न्यायालयों में अपनी-अपनी दलीलों को दोहराया है। उन्होंने अपने-अपने प्रस्तावों के समर्थन में इस न्यायालय और कुछ उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर भी भरोसा किया है। विद्वान वकीलों ने भी व्यापक लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की हैं।

<u>विचार के लिए प्रश्न</u>

10. विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या आवेदन पत्र में की गई त्रुटियां, जिसे अपलोड किया गया था, एक भौतिक त्रुटियां है या एक तुच्छ त्रुटियां है और क्या राज्य अपीलार्थी को उसी के कारण विफल घोषित करने में उचित था?

<u>चर्चा</u>

11. मान लीजिए, अपीलार्थी को कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि भले ही तारीखों में से कोई भी ली गई हो, वह पात्र था; त्रुटियां का भी चयन पर कोई असर नहीं पड़ा और अपीलार्थी स्वयं इस त्रुटियां से अनजान होने पर उन्होंने शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जो उनकी सही जन्म तिथि को दर्शाते थे।

12. तथ्य निर्विवाद हैं। साइबर कैफे से अपलोड किए गए अपीलार्थी के आवेदन में जन्म तिथि का उल्लेख 08.12.1997 के रूप में किया गया था, जबकि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज उनकी जन्म तिथि 18.12.1997 थी। यह भी निर्विवाद है कि यह अपीलार्थी ही है

जिसने शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे। वह उस त्रुटियां से अनजान थे जो उनके आवेदन पत्र में आई थी। यह भी निर्विवाद है कि विज्ञापन में सभी खंड थे जो यह निर्धारित करते थे कि यदि उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी गलत या भ्रामक है, तो आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया जाना था और आवश्यक आपराधिक कार्रवाई भी की जानी थी। इसमें यह भी प्रावधान था कि उम्मीदवारों को अपने 10वें बोर्ड प्रमाण पत्र के अनुसार सही जन्म तिथि भरनी होगी। खंड में आगे कहा गया है कि उम्मीदवार आवेदन पत्र में अपना नाम, पिता का नाम, पता आदि सही ढंग से भरेंगे। इसमें कहा गया है कि दस्तावेजों की जांच करते समय यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। गलत/भ्रामक तरीके से भरे गए आवेदन पत्रों में सुधार का प्रावधान करने वाला एक खंड भी था, जिसमें कहा गया था कि आवेदन शुल्क को फिर से जमा करके और एक नया आवेदन भरकर त्रुटियों को एक बार ठीक किया जा सकता है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अंतिम तिथि पर आवेदन भरने वाले अगले दिन तक आवेदन को सही कर सकते हैं।

13. समान रूप से निर्विवाद तथ्य यह है कि आवेदन भरने के बाद, अपीलार्थी ने लिखित परीक्षा और शारीरिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की। जवाबी हलफनामे में यह भी कहा गया था कि 61 रिक्त पद खाली थे, हालांकि यह प्रस्तुत किया गया था कि यह गोरखा उम्मीदवारों के लिए था।

14. हम राज्य के इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं कि त्रुटियां इतनी गंभीर थी कि गलत या भ्रामक जानकारी का गठन करती है। हम इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर कहते हैं। यहां तक कि राज्य ने भी किसी भी आपराधिक कार्रवाई का सहारा लेने का विकल्प नहीं चुना है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि उन्होंने भी विचार नहीं किया कि इस त्रुटियां को विज्ञापन में निम्नलिखित खंड का उल्लंघन मानते हैंः .

> "ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ने और कृपया निम्नलिखित टैब में उपयुक्त प्रतिक्रिया भरने की सलाह दी जाती है। यदि उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी गलत या भ्रामक पाई जाती है, तो आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा और उम्मीदवार के खिलाफ आवश्यक आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी।"

15. हाल ही में **दिव्या** बनाम **भारत संघ और अन्य** में इस पीठ ने 2023:आई. एन. एस. सीः900 = 2023 (13) स्केल 730, अधिसूचना में उल्लिखित तिथि के बाद पात्रता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को राहत देते हुए एक संकीर्ण अपवाद बनाया गया है। वहाँ, **अजय कुमार मिश्रा** बनाम **भारत संघ और अन्य** मामलों में निर्णय [2016] एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 6563, वर्तमान मामले के तथ्यों के समान एक मामला, उल्लेख किया गया था। **अजय कुमार मिश्रा (ऊपरोक्त)** में, इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति (उस समय उनका अधिपत्य के रूप में) कंडिका 9 में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के लिए बोल रही थीं, जो इस प्रकार हैः

> 9. यह सच है कि जब भी आवेदन पत्र में कोई भौतिक विसंगति देखी जाती है और/या जब किसी दमन और/या गलत प्रतिनिधित्व का पता चलता है, तो आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने और उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दिएजाने के बाद भी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। हालांकि, एक उम्मीदवार के चयन प्रक्रिया में भाग लेने और सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद, उसकी उम्मीदवारी को केवल चूक की गंभीरता की सावधानीपूर्वक जांच के बाद ही रद्द किया जा सकता है, न कि मामूली चूक या त्रुटियों के लिए।
>
> (जोर दिया गया)

तुच्छ त्रुटियों या चूक के लिए अपवाद इस कारण से है कि कानून खुद को छोटी-मोटी बातों से संबंधित नहीं रखता है। इस सिद्धांत को कानूनी उक्ति-डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स में मान्यता प्राप्त है।

16. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अपनी लिखित प्रस्तुतियों में, अपने प्रस्ताव के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया कि जन्म तिथि को भरने में अनजाने में त्रुटियां जब कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है तो यह एक जानबूझकर गलत प्रतिनिधित्व नहीं होगा और तर्क दिया कि उन सभी मामलों में उम्मीदवारों को राहत दी गई थीः

i) **अक्षित कपूर** बनाम **भारत संघ**, 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 10154 [कंडिका 20]

ii) **के. संगीता** बनाम **तमिलनाडु लोक सेवा आयोग** (2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 5075 [कंडिका 9 और 11]

iii) **अनुज प्रताप सिंह** बनाम **संघ लोक सेवा आयोग**, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 10982 [कंडिका 15,16 और 21]

iv) **शुभम तुशीर** बनाम **भारत संघ**, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 9831 [कंडिका 4 और 10]

v) **कर्मचारी चयन आयोग और एक अन्य** बनाम **शुभम तुशीर** दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2020 का एल. पी. ए. संख्या 237

vi) **पूनम पाल** बनाम **एम. पी. ग्रामीण बैंक** (2022) एससीसी ऑनलाइन एमपी 2921 [कंडिका 9-12]

17. वास्तव में, अनुज प्रताप सिंह (उपरोक्त) में, जैसा कि उक्त निर्णय के कंडिका 14 से स्पष्ट है, उम्मीदवार जो पहले बिंदु पर त्रुटियां को ठीक करने में असमर्थ था, उसे मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन जमा करते समय इसे दोहराने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। न्यायालय ने स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया और जन्म तिथि से संबंधित कॉलम को भरने में हुई त्रुटियां को माफ कर दिया।

18. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने चयन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत एक मुद्रित प्रपत्र में विवरण के अपीलार्थी द्वारा सत्यापन की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने उस प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें जन्म तिथि थी। सबसे पहले, प्रपत्र एक मुद्रित प्रपत्र था जो अपीलार्थी द्वारा दी गई जन्म तिथि को दर्शाता था और अपीलार्थी ने 10.03.2018 को मुद्रित प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए थे। हम अपीलार्थी के इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं कि चूंकि अपीलार्थी अपनी गलती से अनजान था, इसलिए उसने मुद्रित प्रपत्र पर यांत्रिक रूप से हस्ताक्षर किए थे। बाद में, 11.06.2018 को, परिणाम के प्रकाशन पर ही अपीलार्थी को त्रुटियां का एहसास हुआ। हम नहीं सोचते कि अपीलार्थी को इस तुच्छ त्रुटियां के लिए दंडित किया जा सकता है जिससे अंतिम परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार की त्रुटियाँ, जैसा कि वर्तमान मामले में देखा गया है, जो अनजाने में होती हैं, गलत निरूपण या जानबूझकर दमन का गठन नहीं करती हैं।

19. इस मामले में, अपीलार्थी ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया है और सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। आवेदन में त्रुटियां मामूली है जिसने चयन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाई। इस तिल पहाड़ी से पहाड़ बनाना राज्य के लिए उचित नहीं था। शायद साइबर कैफे का दुर्लभ वातावरण, अपीलार्थी से बेहतर हो गया। उन्होंने त्रुटियां पर ध्यान देना छोड़ दिया और यहां तक कि प्रस्तावित सुधारात्मक तंत्र का लाभ उठाने में भी विफल रहे। तत्काल मामले में, हम मौजूद जमीनी वास्तविकताओं की ओर नेल्सन की नज़र नहीं मोड़

सकते। 2021 के सी. ए. संख्या 6983 में दिनांकित 22.11.2021 आदेश में [**प्रिंस जयबीर सिंह** बनाम **भारत संघ और अन्य.**], इस न्यायालय ने ठीक ही कहा कि यद्यपि प्रौद्योगिकी एक बड़ा प्रवर्तक है, लेकिन साथ ही एक डिजिटल विभाजन भी है।

20. उच्च न्यायालय के समक्ष जवाबी हलफनामे में उदाहरण के रूप में उद्धृत मामलों में से एक में, **पंकज पासवान** बनाम **बिहार राज्य एक अन्य**., 2015 एस. सी. सी. लाइन पटना 8739 में, राज्य ने बचाव किया था कि कई उम्मीदवारों ने एक से अधिक स्थानों पर आवेदन किया था और इसलिए तारीख 13 में जानबूझकर जन्म तिथि में बदलाव किया जा सकता है, एक से अधिक जिलों या क्षेत्रों में चयन प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान मामले में ऐसी कोई याचिका नहीं ली गई है। यदि ऐसा कोई उपकरण या चाल अपनाई गई होती, तो राज्य ने आसानी से इसका पता लगा लिया होता और इसे न्यायालय के समक्ष रखा होता। यह तथ्य कि ऐसा नहीं किया गया है, यह दर्शाता है कि अपीलार्थी द्वारा कोई चाल या उपकरण का सहारा नहीं लिया गया था। यह एक छोटी सी त्रुटियां है जो एक वास्तविक और प्रामाणिक त्रुटियां प्रतीत होती है। इसके लिए अपीलार्थी को दंडित करना अन्याय होगा।

21. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित प्रस्तुतियों में कहा कि निर्देशों में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार शारीरिक पात्रता परीक्षा में समान अंक प्राप्त करते हैं, तो अंतिम योग्यता सूची में उनकी सापेक्ष रैंक उनकी जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। प्रस्तुतिकरण में निहितार्थ यह है कि जन्म तिथि एक महत्वपूर्ण पहलू है। उस आधार पर, वह प्रस्तुत करता है कि रद्द करने को बरकरार रखा जाना चाहिए। हम प्रस्तुतिकरण में योग्यता नहीं पाते हैं। जन्म की मूल तिथि, जैसा कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में 18.12.1997 उपलब्ध है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है

कि अपीलार्थी की जन्म तिथि वास्तव में 18.12.1997 थी। इसे ध्यान में रखते हुए, हम निर्देशों में उक्त खंड को अपीलार्थी के चयन में बाधा के रूप में नहीं देखते हैं।

22. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने भी लिखित प्रस्तुतियों में, **योगेश कुमार और अन्य** बनाम **दिल्ली की एन.सी.टी. सरकार और अन्य** में इस न्यायालय के फैसले का हवाला दिया है। (2003) 3 एससीसी 548 को हवाला दिया। उक्त निर्णय स्पष्ट रूप से अलग है। वहाँ मुद्दा चयन में अयोग्य व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति देने का था। जबकि निर्धारित पात्रता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या मैट्रिक स्तर पर आवश्यक भाषा में वैकल्पिक विषय के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से इंटरमिडिएट या समकक्षी, बीएड डिग्री वाले उम्मीदवारों ने सहायक शिक्षक के रुप में नियुक्ति मांगी थी। उनके दावे को नकारते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि बी. एड. योग्यता को शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र से अधिक योग्यता के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि प्रशिक्षण की प्रकृति के लिए प्रमाण पत्र देना और डिग्री देना पूरी तरह से अलग था। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा कि नियमों से विचलित होने और अयोग्य व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति देने से कई अन्य लोग वंचित हो जाएंगे जो इस पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। **योगेश कुमार (उपरोक्त)** का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय भी उतने ही अलग हैं इनमें **रोहित कुमार और एक अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य,** 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 1219 और **प्रदीप कुमार बनाम भारत संघ और अन्य**, 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 239।

23. **रोहित कुमार (उपरोक्त)** के मामले में, निर्विवाद तथ्य, जैसा कि निर्णय के कंडिका 10 से स्पष्ट है, यह था कि उम्मीदवार को दो मामलों में असफल घोषित किया गया था, अर्थात्, उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया गया ओ. बी. सी. प्रमाण पत्र विज्ञापन में उल्लिखित प्रारूप

के अनुसार नहीं था और इसके अतिरिक्त इस आधार पर कि प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख ऑनलाइन आवेदन में गलत तरीके से उल्लिखित की गई थी।

24. **प्रदीप कुमार (उपरोक्त)** में, पहचान प्रमाण (आधार कार्ड) अपलोड नहीं किया गया था और इसके बजाय उम्मीदवार की स्वयं की तस्वीर अपलोड की गई थी। हम पाते हैं कि उपरोक्त दो निर्णय ऊपर बताए गए कारणों के आधार पर तथ्यों के आधार पर अलग-अलग हैं।

25. इस मामले के विशिष्ट तथ्यों पर, जिस पृष्ठभूमि में त्रुटियां हुई, उस पर विचार करते हुए, हम रद्दीकरण को दरकिनार करने के लिए इच्छुक हैं। हम डिवीजन बेंच के इस निष्कर्ष से प्रभावित नहीं हैं कि वेब पर घोषित परिणामों को रद्द करने की कोई प्रार्थना नहीं की गई थी। रिट याचिका में प्रार्थना खंड को पढ़ने से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी ने एक परमादेश के लिए प्रार्थना की थी जिसमें उत्तरदाताओं को अपनी जन्म तिथि को 18.12.1997 मानते हुए उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश और नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए निर्देश भी मांगा गया था। एक रिट कोर्ट के पास राहत देने की शक्ति होती है। न्याय को तकनीकीता की वेदी पर नहीं छोड़ा जा सकता है।

<u>निष्कर्ष</u>

26. ऊपर बताए गए कारणों के लिए, हम 2019 के एल. पी. ए. संख्या 1271 दिनांक 22.08.2022 में पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले को दरकिनार करते हैं और प्रतिवादी-राज्य को निर्देश देते हैं कि केंद्रीय चयन बोर्ड (कांस्टेबल भर्ती), पटना द्वारा जारी 2017 की विज्ञापन संख्या 1 के तहत आयोजित चयन प्रक्रिया में जन्म तिथि 18.12.1997 के साथ अपीलार्थी को एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में माना जाए जो "उत्तीर्ण" हो गया है। हम आगे निर्देश देते हैं कि यदि अपीलार्थी अन्यथा अयोग्य नहीं है, तो अपीलार्थी के मामले पर विचार किया जाए और आवश्यक नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। हम आगे निर्देश देते हैं कि

कोई रिक्ति नहीं होने की स्थिति में, इस मामले के विशेष तथ्यों पर नियुक्ति पत्र जारी करना होगा। हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निर्देश देते हैं। हम आगे निर्देश देते हैं कि राज्य उस स्थिति में अगली भर्ती में रिक्तियों को समायोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसका वे आने वाले वर्षों में सहारा ले सकते हैं। हम राज्य की लिखित प्रस्तुतियों से देखते हैं कि 2023 के विज्ञापन संख्या 1 में 21,391 रिक्तियों को अधिसूचित किया गया है और यह कहा गया है कि चयन की प्रक्रिया जारी है। हम उक्त बयान को अभिलेख में रखते हैं। हम आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उपरोक्त दिशा-निर्देश के अनुपालन का निर्देश देते हैं आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उपरोक्त निर्देश दिया जाए।

27. उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

अनिकेत ज्ञान द्वारा हेडनोट तैयार किया गया केस का परिणाम: अपील की अनुमति